भारत में मूल्य-अर्जन अनुपात

1659. **श्री राम जेटमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1991 के "स्टेट्समैन" दैनिक समाचार-पत्र में "प्राइस अर्निंग रेशो लो इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात का प्रतिशत कम होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस अनुपात को बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(घ) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) जी, हां। 5 मई, 1991 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, भारतीय पूंजी बाजार का औसत मूल्य-अर्जन अनुपात जापान, इंडोनेशिया, ताईवान, मलेशिया, और थाईलैंड जैसे कुछ अन्य देशों की तुलना में कम बताया गया है।

(ख) इन देशों में अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य, अर्जन-अनुपात, अलग-अलग बाजार पूंजीकरण दरों, अलग-अलग ऋण इक्विटी अनुपातों की मात्राओं, शेयर इन्ट्रूमेंट्स की सीमित आपूर्ति, जिसके कारण शेयर मूल्य बढ़ते हैं, आदि के कारण हो सकता है। इनमें से कुछ अर्थ-व्यवस्थाओं में उच्च विकास की संभावनाओं के कारण भी उच्च मूल्य-अर्जन अनुपात हो सकता है।

(ग) जी, नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य-अर्जन अनुपात में वृद्धि से पूंजी बाजार की समृद्ध हालत का पता लगता हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रायगढ़ में खाद्य-प्रसंस्करण एककं

1660. **कुमारी सईदा खातून :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश में, रायगढ़ में जहां आदिवासी किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की अच्छी खेती करते हैं, एक खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

( ) मध्य प्रदेश में अब तक कितने खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों को स्वीकृति दी गई है तथा जब से यह नया मंत्रालय बना है तब से लेकर अब तक वहां कितने उद्योग स्थापित किए गए ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में टमाटर और दूसरे फल प्रसंस्करण एककों की स्थापना पर एक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट की इस मंत्रालय में जांच की गई है और मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि० से कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेज मंगाये गये हैं। इस परियोजना में टमाटर, पपीता, अमरूद आम और कटहल का प्रसंस्करण शामिल है। भारत सरकार 75% तक अनुदान सहायता देकर इस परियोजना को स्थापित करने में मदद करेगी।

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड उज्जैन में एक पोषाहार संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित सेक्टर में हैं अतः यह सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती परन्तु मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दुर्ग स्थित भिलाई इंजीनियरिंग कंपनी को टमाटर पेस्ट, आम और अमरूद सांद्रण तैयार करने के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं। मध्य प्रदेश राज्य में एक दूध उत्पादन यूनिट को भी स्वीकृति दी गई है। मार्डन-फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के इस राज्य में दो संयंत्र हैं जो क्रमशः ब्रेड और तेल तैयार करने के लिए इन्दौर और उज्जैन में स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न फलों और सब्जियों पर आधारित उत्पाद तैयार करने लिए फल उत्पाद आदेश 1955 के अधीन 31-12-90 तक 65 लाइसेंस जारी कर दिए गये हैं।

Proposal to attract Japanese electronics firms

1661. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAMSINH RATHWA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to attract large Japanese electronics firms to start their units in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Japanese firms have demanded changes in industrial policy to facilitate the setting up of their units in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) The Statement on Industrial Policy dated 24th July, 1991 has recognised the need for a more dynamic relationship between domestic and foreign industry in terms of both technology and investment. This applies to large Japanese electronic firms also. Japanese firms have not demanded any specific changes in the Industrial Policy of India.

Bogus computer training institutions

1662. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAMSINH RATHWA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of computer training institutions are making various claims about their training courses;

(b) if so, whether there is a proposal for standardisation of their courses;

(c) whether the Department of Electronics would accredit these institutions;

(d) whether any complaint has been received about some of the claims of these institutions being bogus or misleading; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of India, Department of Electronics vide Resolution, dated 16th August, 1990, have announced a scheme under which private sector computer training institutes meeting the defined quality and service standards would be given accreditation for conducting certain specified courses viz. O (Foundation). A (Advance Diploma). B (Graduate) and C (Post Gradudate) levels computer courses.

(d) and (e) There have been a few instances of inflated claims being made by the institutions which have been given accreditation under the scheme. Such institutions have been/are being directed to rectify their advertisements etc. in this regard. Some of them have already responded while others are in the process of doing so.